1996 में जीडीए के सलाहकार के रूप में मैंने सरकार को सुझाव दिया था कि यूपी की सीमा के भीतर ही अप्सरा बॉर्डर पार करते ही दायीं ओर यानी रेलवे लाइन और जीटी रोड के बीच की सरकारी जमीन पर एक बड़ा ट्रक टर्मिनल विकसित किया जाए।

-आर. जी. गुप्ता, डीडीए के पूर्व कमिश्नर (प्लानिंग) और जीडीए के सलाहकार रहे पॉलिसी एंड सिटी प्लॉनर

यूपी के ढीले रवैये से फ्लाईओवर लेट

अप्सरा बॉर्डर के ट्रैफिक की कहानी, आरडब्ल्यूए की जबानी

दिल्ली की सीमाएं बदल रही हैं और सच तो यह है कि अब सीमाएं रही ही नहीं। प्रशासनिक और राजनीतिक सीमाएं भी अक्सर टूट जाती हैं। इसलिए ग्रेटर दिल्ली का सपना तो अपने आप ही पूरा हो रहा है। यह बात *एनबीटी* द्वारा आयोजित रू-ब-रू कार्यक्रम में साफ तौर पर नजर आई। इसीलिए आरडब्ल्यूए के प्रतिनिधियों ने लगे हाथों ट्रैफिक के अलावा दूसरी समस्याओं पर भी विधायकों और पार्षदों का ध्यान खींच लिया, साथ ही उन्हें दुरुस्त करने के उपाय भी सुझाए। *राकेश पाराशर* और *राज़ेश सरोहा* पेश कर रहे हैं इन इलाकों की आरडब्ल्यूए के साथ हुई बातचीत से निकली रिपोर्ट :

एनबीटी द्वारा 'दिल्ली से ग्रेटर दिल्ली' अभियान के तहत जब दिल्ली और यूपी के प्रतिनिधियों को एक मंच पर लाकर आरडब्ल्यूए से रू-ब-रू कराया गया तो यह बात सभी ने स्वीकार की कि अगर यूपी सरकार का रुख पॉजिटिव होता तो अप्सरा बॉर्डर का फ्लाईओवर तीन साल पहले ही बन जाता।

दरअसल, अप्सरा बॉर्डर पर बन रहे फ्लाईओवर और अंडरपास का 200 मीटर का हिस्सा गाजियाबाद में आता है। इस पूरे प्रोजेक्ट पर दिल्ली सरकार ही खर्चा कर रही है और निर्माण कार्य भी करा रही है। वह यूपी की जमीन पर काम करने के लिए यूपी सरकार से अनुमति चाहती थी लेकिन इस अनुमति के लिए पहले मुलायम सिंह सरकार और फिर मायावती सरकार से गुहार करनी पड़ी। जो काम एकाध महीने में हो जाना चाहिए था, उसके लिए दिल्ली सरकार को तीन साल तक इंतजार करना पड़ा।

यह बात यमुनापार विकास बोर्ड के अध्यक्ष तथा विधायक डॉ. नरेंद्र नाथ ने भी जोरशोर से कही और विधायक वीर सिंह धिंगान ने भी। यहां तक कि उत्तर प्रदेश से आए विधायक सुनील शर्मा ने तो कहा कि दिल्ली का जितना विकास हो रहा है, उसे देखते हुए हम तो यही कामना करते हैं कि गाजियाबाद को दिल्ली में ही मिला दिया जाए। आरडब्ल्यूए की ओर से यूपी सरकार के प्रति नाराजगी जताई गई। प्रतिनिधियों ने कहा कि रोड नंबर- 56 पर गाजीपुर से लेकर अप्सरा बॉर्डर तक बहुत-सा काम होना है क्योंकि यहां अगले कुछ समय में ही तीन लाख लोग आकर बसने वाले हैं। चूंकि दिल्ली सरकार ने कई प्रोजेक्ट तैयार किए हैं और यूपी से तालमेल के बिना कोई काम पूरा नहीं होगा, इसलिए यूपी से पहले ही लिखा लेना चाहिए कि दिल्ली सरकार अगर उसकी जमीन पर काम करती है तो उसे किसी तरह की आपत्ति नहीं होगी।

डॉ. नरेंद्र नाथ ने बताया कि एंट्री पॉइंट की हालत सुधारने के लिए दिल्ली सरकार ने यहां थ्री लेयर ट्रैफिक की योजना बनाई। जाहिर है कि इस फ्लाईओवर का दिल्लीवालों को तो फायदा होना ही था क्योंकि यहां से भीड़भाड़ खत्म हो जाएगी लेकिन उससे ज्यादा फायदा गाजियाबाद को होगा। इसलिए यूपी सरकार से 200 मीटर जमीन पर काम करने की अनुमति मांगी गई लेकिन यह अनुमति पूरे तीन साल में आई। यहां तक कि मुझे भी इंजीनियरों को लेकर लखनऊ जाना पड़ा। मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने भी यूपी सरकार को कई बार लिखा। अगर इस काम में देरी नहीं की जाती तो तीन साल पहले ही फ्लाईओवर तैयार हो जाता।

गाजियाबाद के बीजेपी विधायक सुनील शर्मा ने इस मामले में मुख्यमंत्री मायावती की आलोचना की। उन्होंने माना कि इस मामले में किसी तरह की राजनीति नहीं होनी चाहिए और क्षेत्र के विकास पर जोर दिया जाना चाहिए लेकिन बीएसपी एंट्री पाइंट पर ट्रैफिक सुचारु करने के बजाय मूर्तियां लगवाने में जुटी है। रोड नंबर -56 के साथ-साथ दिल्ली की सीमा से

आनंद विहार की ओर